



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plexh/Cir/861

10.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: डिजिटल व्यापार सुविधा विधेयक, 2026' पर टिप्पणियों के लिए अनुरोध**

यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में भारतट्रेडनेट को लागू करने के लिए प्रारंभिक कदम के रूप में 'डिजिटल व्यापार सुविधा विधेयक, 2026' का मसौदा तैयार किया है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।

इस मसौदा विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार दस्तावेजों को वैधानिक मान्यता प्रदान करने, विश्वसनीय डिजिटल सत्यापन तंत्र को सक्षम बनाने और व्यापार अभिलेखों के सुरक्षित सीमा पार आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित लिंक से इस विधेयक के मसौदे को पढ़ें और 27 फरवरी, 2026 से पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणियां और सुझाव साझा करें ताकि इन्हें संकलित करके डीजीएफटी के साथ साझा किया जा सके।

<https://drive.google.com/file/d/1JuPPF5DBmprjGwdsBvM-UgwGf5I6OCEa/view?usp=sharing>

सदस्य अपनी प्रतिक्रिया [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) या [shilpa@plexconcil.org](mailto:shilpa@plexconcil.org) पर भेज सकते हैं।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल